दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, रविवार 03 मार्च 2024 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-06, अंक- 156

महत्वपूर्ण एवं खास

राष्ट्रपति कार्यालय का बड़ा फैसला, अब इस समय तक अमृत उद्यान का दौरा कर सकेंगे लोग

नई दिल्ली (आरएनएस)। अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि लोग अब शाम 6 बजे तक राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान का दौरा कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 31 मार्च, 2024 तक जनता के दर्शन के लिए खुला रहेगा। उद्यान उत्सव-1, 2024 के तहत अमृत उद्यान खुला है। राष्ट्रपति सचिवालय ने कहा कि लोग सोमवार को छोडक़र सप्ताह में छह दिन सुबह 10.00 बजे से शाम 06.00 बजे (अंतिम प्रवेश – 05.00 बजे) के बीच उद्यान का दौरा कर सकते हैं। पहले, उद्यान सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे (अंतिम प्रविष्टि – शाम 4.00 बजे) के बीच खुलता था। वॉक-इन आगंतुकों को राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 12 के पास सुविधा काउंटर या स्वयं सेवा कियोस्क पर पंजीकरण कराना होगा।

मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर थाना पुलिस और बदमाशों के बीच बीती देर रात मुठभेड़ हो गई। इसमें गोली लगने से घायल एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका एक साथी फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश के पास से चोरी की दो बैट्री, एक कार और अवैध हथियार भी मिला है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक थाना मीरापुर पुलिस द्वारा गांव रूमालपुरी के पास चेकिंग की जा रही थी, तभी सामने से आ रही एक वर्ना कार को रुकने का इशारा किया गया। लेकिन कार सवारों ने कार को तेजी से चलाते हुए भागने का प्रयास किया। इस पर पुलिस ने पीछा शुरू किया, तो बदमाशों ने कार से उतरकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से बदमाश सरफराज घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से एक तमंचा, 1 खोखा कारतूस व 1 जिन्दा कारतूस, चोरी की दो बैट्री और एक वर्ना कार बरामद की गई। बदमाशों ने गांव कासमपुर खोला में स्थित मोबाइल टावर से बैट्री चोरी की थी।

भूस्खलन के कारण श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध

श्रीनगर (आरएनएस)। लगातार बारिश के कारण हुए कई भूस्खलनों ने शनिवार को श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि बनिहाल और रामबन सेक्टर के बीच लगातार बारिश के कारण हुए कई भूस्खलनों के चलते श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। अधिकारियों ने कहा, शनिवार को राजमार्ग पर किसी भी यातायात की अनुमति नहीं दी जाएगी। इलाके में बारिश रुकने के बाद भूस्खलन हटाने का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर खराब पैच के कारण पिछले एक सप्ताह से इस राजमार्ग पर केवल एक तरफा यातायात की अनुमति थी। इस बीच, भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर-लेह, मुग़ल रोड, सिंथन-किश्तवार, बांदीपोरा-गुरेज़ और कुपवाड़ा-तंगधार की सडक़ें अवरूद्ध हो गई है।

बड़ी टेक कंपनियों के लिए केंद्र की एडवाइजरी, एआई मॉडल लॉन्च करने से पहले लेनी होगी अनुमति

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र ने शनिवार को एआई के दुरुपयोग पर बड़े इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की कड़ी आलोचना की और कहा कि सभी मध्यस्थों को किसी भी पूर्वाग्रह या भेदभाव की अनुमति नहीं देनी चाहिए या चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को खतरे में नहीं डालना चाहिए। उसने कहा कि देश में कोई भी एआई मॉडल लॉन्च करने से पहले सरकार की अनुमति अवश्य लें। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि आईटी मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि मध्यस्थ या प्लेटफॉर्म नए आईटी नियम, 2021 के तहत उल्लिखित उचित जाँच दायित्वों को पूरा नहीं कर रहे हैं।

पिछले साल दिसंबर में जारी एडवाइजरी के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अब कहा है कि सभी मध्यस्थों/प्लेटफॉर्मों को सलाह दी जाती है कि वे एआई के कारण यूजरों को होने वाले नुकसान और गलत सूचना,

विशेष रूप से डीपफेक संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

डिजिटल प्लेटफार्मों को तत्काल प्रभाव से नए दिशानिर्देशों का पालन करने और इस एडवाइजरी के 15 दिन के भीतर मंत्रालय को की गई कार्रवाई-सह-स्थिति रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। मंत्री ने कहा, हाल ही में गूगल जेमिनी एआई विवाद के आलोक में, एडवाइजरी अब विशेष रूप से एआई से संबंधित है। डिजिटल प्लेटफॉर्म को पूरी जवाबदेही लेनी होगी और यह कहकर नहीं बच सकते कि ये एआई मॉडल परीक्षण के चरण में हैं।

सोशल मीडिया मीडिएटर्स को परीक्षण के तहत एआई प्लेटफार्मों को लेबल करना होगा, सरकार की अनुमति लेनी होगी और अंतिम यूजरों की सहमति भी लेनी होगी कि उनके एआई मॉडल और सॉफ्टवेयर में त्रुटियां होने की संभावना है ताकि नागरिकों को उनके परिणामों के बारे में पता चल सके।

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी मध्यस्थों या प्लेटफार्मों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई मॉडल/एलएलएम/जेनरेटिव एआई, सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम का उपयोग अपने यूजरों को किसी भी चीज़ को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, स्टोर, अपडेट या साझा करने की अनुमति नहीं देता है।

नए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि परीक्षण से गुजर रहे/अविश्वसनीय एआई मॉडल का उपयोग और भारतीय इंटरनेट पर यूजरों के लिए इसकी उपलब्धता भारत सरकार की स्पष्ट अनुमति के साथ की जानी चाहिए और उत्पन्न आउटपुट की संभावित और अंतर्निहित गलतियों या अविश्वसनीयता को उचित रूप से लेबल करने के बाद ही ऐसा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, 'सहमति पॉपअप' तंत्र का उपयोग यूजरों को उत्पन्न आउटपुट की संभावित और अंतर्निहित गलतियों या अविश्वसनीयता के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करने के लिए किया जा सकता है।

आईटी मंत्रालय की सलाह में कहा गया है, यह दोहराया जाता है कि आईटी अधिनियम और/या आईटी नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर मध्यस्थों या प्लेटफार्मों या इसके यूजरों की पहचान होने पर संभावित दंडात्मक परिणाम होंगे, जिसमें आईटी अधिनियम और आपराधिक संहिता के कई अन्य कानूनों के तहत अभियोजन शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा

- **रायगढ़ लोकसभा सीट के लिए राधेश्याम राठिया, रायपुर से बृजमोहन के नाम पर मुहर**

रायपुर (आरएनएस)। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीद्वारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची मे देश के 16 राज्यों के 195 सीटों के लिए नामों का ऐलान कर दिया गया है। जिसमें छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों के लिए प्रत्याशियो के नामों की घोषणा कर दी गई है।

जारी सूची के अनुसार

रायपुर लोकसभा सीट के लिए बृजमोहन अग्रवाल,दुर्ग लोकसभा सीट के लिए विजय बघेल, राजनांदगांव लोकसभा सीट के लिए संतोष पांडेय,

बिलासपुर लोकसभा सीट के लिए तोखन साहू, कोरबा लोकसभा सीट के लिए सरोज पांडेय, रायगढ़ लोकसभा सीट के लिए राधेश्याम राठिया,

बस्तर लोकसभा सीट के लिए दिनेश कश्यप,कांकेर लोकसभा सीट के लिए भोजराज नाग,सरगुजा लोकसभा सीट के लिए चिंतामणि महाराज,

महासमुंद लोकसभा सीट के लिए रूप कुमारी चौधरी तथा जांजगीर लोकसभा सीट के लिए कमलेश जांगड़े के नाम पर मुहर लगी है।

भारत का एक और दुश्मन खत्म : लश्कर की खुफिया शाखा के चीफ और 26/11 हमले के मास्टरमाइंड की मौत

मुंबई (आरएनएस)। भारत के दुश्मनों का एक-एक कर नाश हो रहा है। कुछ समय से पाकिस्तान में छिपे बैठे कई आतंकियों की मौत हो चुकी है। किसी की मौत प्राकृतिक तौर पर हुई तो किसी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। इसी कड़ी में पाकिस्तान में लश्कर आतंकी आजम चीमा की पाकिस्तान के फैसलाबाद में मौत हो गई। आजम चीमा 26/11 हमले का मास्टरमाइंड भी है।

70 वर्षीय चीमा आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की खुफिया शाखा का प्रमुख था। उसकी मौत के बाद पाकिस्तानी के जिहादियों में भय का संचार हो गया है। जानकारी के मुताबिक, लश्कर आतंकी चीमा अपने जीवन के शुरुआती समय में पाकिस्तान के बहावलपुर में अपने बीवी-बच्चों के साथ रहता था। ये वक्त 2000 का दशक था। वह पंजाबी बोलता था। पाकिस्तान में अक्सर उसे अपने बॉडीगार्ड्स के साथ लैंडक्रूजर कार में शान से घूमते देखा गया था। वह बहावलपुर में चल

रहे आतंकी शिविरों में इस्लामिक जिहादियों का ब्रेनवाश करने के लिए चीफ जनरल हामिद गुल, ब्रिगेडियर रियाज और कर्नल रफीक को बहावलपुर ले आया था। इतना ही नहीं चीमा के अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन के साथ भी संबंध थे। उसने 2008 में पाकिस्तान के बहावलपुर में लश्कर के कमांडर के तौर पर काम किया था और जकी उर रहमान लखवी का एडवाइजर भी रहा। रिपोर्ट के मुताबिक, आतंकी चीमा को मानचित्र का अच्छा अनुभव था वो भारत के मैप पर आतंकियों को देश के प्रमुख सुरक्षा प्रतिष्ठानों के बारे में बताता था।

महादेव बुक के फरार चल रहे मुख्य सरगना रतन लाल जैन के खिलाफ ईडी ने शुरू की रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया

नई दिल्ली/रायपुर (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव बुक के अवैध सट्टेबाजी पर लगाम लगाने के लिए फरार चल रहे मुख्य सरगना रतन लाल जैन के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दे की रतन लाल जैन और गिरीश तलरेजा भोपाल के मूल रूप से स्थानीय निवासी है। दोनों ने सट्टेबाजों के रूप में पहले भोपाल मे ही काम शुरू किया था, लेकिन बाद में दोनों दुबई चले गए जहां से वे भारत में सबसे बड़े सट्टेबाजी नेटवर्क में से एक को संचालित करते है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों ने कथित तौर पर 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की अभीतक इस अवैध कारोबार से कमाई कर चुके है।

इन दोनों के खिलाफ पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए की रोकथाम के तहत एक विशेष अदालत द्वारा उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, मामले मे आगे रतन लाल जैन के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए विदेश मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।

जानिए रेड कॉर्नर नोटिस का क्या होता है मतलब और कैसे करता है काम

रेड कॉर्नर नोटिस उन व्यक्तियों के खिलाफ जारी किया जाता है जो या तो अभियोजन के लिए वांछित हैं या रेड कॉर्नर नोटिस के तहत सजा काटने के लिए दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से अनुरोध किया जाता है कि वे उक्त व्यक्तियों का पता लगाने और गिरफ्तार करने के लिए लंबित प्रत्यर्पण अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल है।

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल ने अपने सभी 195 सदस्य देशों में एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो एनसीबी नियुक्त किया है, ये ब्यूरो इंटरपोल और भारत में उस सदस्य देश की संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच संपर्क के एकल बिंदु के रूप में काम करते हैं।

इन इंडिया द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई इसकी आधिकारिक एनसीबी है जिसे भारत के कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा आवश्यक रूप से भगोड़े अपराधियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस को बनाए रखने और अद्यतन करने का काम सौंपा गया है।

महादेव बुक बैटिंग ऐप मामले में कई व्यक्तियों की गिरफ्तारी देखी गई है हाल ही में गिरफ्तार व्यक्तियों में चंद्रभूषण वर्मा नाम का एक एएसआई शामिल है, जो सतीश चंद्राकर नाम का मास्टरमाइंड का रिश्तेदार है और हवाला ऑपरेटर अनिल दममानी और सुनील दमानी वर्मा पर रिश्वत की राशि लेने का आरोप है। वर्मा पर 65 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने और अपने अधीन अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को वितरित करने का आरोप लगाया, जबकि अन्य पर अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क के संचालन को अंजाम देने और देश से बाहर आय को लूटने का संदेह है।

चुनाव आयोग ने किया स्पष्ट

किसी भी तरह की गड़बड़ी या पक्षपातपूर्ण घटना के लिए डीएम-एसपी होंगे जिम्मेदार

लखनऊ (आरएनएस)। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होगा। अगर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में कोई गड़बड़ी या पक्षपातपूर्ण की घटना पाई जाती है तो इसके जिम्मेदार जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक होंगे। इन बातों का जिक्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को विधान भवन के तिलक हाल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन को लेकर की जा रही तैयारियों से आयोग संतुष्ट है।

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सबसे पहले अपने तीन दिवसीय दौरे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की टीम ने दौरे के पहले दिन राष्ट्रीय एवं राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी।

इस दौरान विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों की तरफ से आयोग की टीम को कुछ सुझाव एवं आग्रह प्राप्त हुए थे, जिन पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने एक-एक करके अपनी बात रखी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मतदान के बाद सभी ईवीएम मतदान केंद्र से स्ट्रांग रूम तक सरकारी वाहन में भेजे जाएंगे। चुनाव के दौरान पहले प्रत्याशियों को 50-50 चेक की चार चेकबुक बैंक से बारी-बारी से प्राप्त होती थी। इससे उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था क्योंकि चुनाव के दौरान छोटे-छोटे खर्चे भी प्रत्याशियों को चेक के माध्यम से करने पड़ते थे। इस बार प्रत्याशी 200 चेक की चेकबुक बैंक से प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में बैंकों को निर्देशित किया जा चुका है। मतदाताओं की सुलभता एवं मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए हाईराइज बिल्डिंग में मतदान केंद्र बनाएं जाएंगे।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को तीन बार समाचार पत्रों में अपनी आपराधिक छवि के बारे में प्रकाशित करवाना पड़ेगा। इसके अलावा राजनीतिक दलों को भी समाचार पत्रों में यह प्रकाशित करवाना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने अपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी का चुनाव किया है। पूर्व में हुए चुनावों में जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कम होता आया है, उनका चिन्हांकन कर वहां पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने का आयोग की तरफ से प्रयास किया जा रहा है।

आयोग ने बताया कि इस बार प्रकाशित हुए इलेक्ट्रोल रोल में उत्तर प्रदेश में अब तक 15 करोड़ 29 लाख 22 हजार मतदाता हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या 7.15 करोड़ है। वहीं, 100 वर्ष से अधिक के मतदाताओं की संख्या 31 हजार है। इस बार थर्ड जेंडर, दिव्यांगजन और नए मतदाताओं की संख्या बढ़ी है।

उन्होंने कहा कि 2024 में सभी को समान अवसर मिलेंगे। अफसरों और पुलिस को निष्पक्ष तरीके से काम करने का निर्देश दिया गया है। चुनाव में धन और बाहुबल का प्रयोग नहीं होगा। इस बार के चुनाव में तकनीक का सर्वाधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बार तीन एप लाए जा रहे हैं। एक एप से मतदाता चुनाव में होने वाले प्रलोभन, शराब और पैसों के वितरण के बारे में सीधे चुनाव आयोग से शिकायत कर सकते हैं।

बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट : सीसीटीवी में आरोपी का चेहरा आया सामने- एआई की मदद से पहचान करेगी पुलिस

बेंगलुरु (आरएनएस)। बेंगलुरु के मशहूर रामेश्वरम कैफे में हुए आईडी ब्लास्ट में 10 लोग घायल हो गए हैं। कैफे में हुए ब्लास्ट की लेटेस्ट वीडियो भी सामने आई है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी का चेहरा साफ नहीं दिख सका। ऐसे में पुलिस अब आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की मदद से आरोपी की पहचान करेगी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी 25 से 30 साल का शख्स है।

कर्नाटक के डी शिवकुमार ने कहा कि पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है। सीसीटीवी में कैप्चर उसके चेहरे को फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से मैच कराया जा रहा है। इससे उसे ट्रैक किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि मास्क लगाए हुए एक व्यक्ति कैफे के पास बस से उतरता है और 11:30 बजे कैफे में दाखिल होता है। इसके बाद वह इडली ऑर्डर करता है, काउंटर पर पेमेंट करके टोकन लेता है। इसके बाद 11:45 बजे एक बैग को डस्टबिन के पास रखकर चला जाता है। एक घंटे बाद इसी बैग में टाइमर के जरिए धमाका किया गया। इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज अभी सामने नहीं आया है। जो सीसीटीवी फुटेज और फोटोज अभी सामने आए हैं, वो भी आधिकारिक सोर्स से नहीं मिले हैं। ये सोशल मीडिया पर हैं।

मोदी सरकार का बड़ा कदम, निजी क्षेत्र के 25 विशेषज्ञ प्रमुख पदों पर होंगे भर्ती

नई दिल्ली (आरएनएस)। शासकीय कार्यों की सुगमता को और बेहतर बनाने के वास्ते मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत निजी क्षेत्र के 25 विशेषज्ञ जल्द ही केंद्र में प्रमुख पदों पर नियुक्त किए जाएंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में तीन संयुक्त सचिवों और 22 निदेशकों/उप सचिवों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आमतौर पर संयुक्त सचिव, निदेश और उप सचिव के पद अखिल भारतीय सेवाओं भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) और समूह ए की अन्य सेवाओं के अधिकारियों के पास होते हैं।

अधिकारियों ने कहा कि इन विशेषज्ञों की सीधी भर्ती (सरकारी विभागों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति) की जा रही है। इसका मकसद सरकार में नई प्रतिभाओं को शामिल करना है। सीधी भर्ती योजना का शुभारंभ 2018 में किया गया था। इसके तहत संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के स्तर पर भर्ती की जाती है। इन स्तरों पर अधिकारी नीतियां बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस प्रक्रिया से आने वाले अधिकारी बाद में सरकारी प्रणाली का अभिन्न अंग बन जाते हैं। 2018 में शुरू की गई लेटरल एंट्री स्कीम के तहत संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव स्तर पर भर्तियां की जाती हैं। इन स्तरों पर अधिकारी नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो अधिकारी पार्श्व प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से आते हैं वे सरकारी प्रणाली का अभिन्न अंग बन जाते हैं। कार्मिक मंत्रालय ने जून 2018 में पहली बार पार्श्व प्रवेश मोड के माध्यम से 10 संयुक्त सचिव-रैंक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इन पदों के लिए भर्ती संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा निकाली गई थी।

पीएम मोदी ने बंगाल को 15,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की दी सौगात

कृष्णानगर (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में 15,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने नादिया जिले के कृष्णानगर में आज एक आधिकारिक समारोह में इन परियोजनाओं का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं से बंगाल को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और अधिक निवेश आएगा। उन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण के लिए राज्य को बिजली पर आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है जो औद्योगिक विकास, रेलवे नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों में मदद करती है।

मोदी ने कहा कि उन्हें बंगाल में 11,000 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है। एक बार अत्यधिक विकसित भारत के स्वतंत्र होने के तुरंत बाद उपेक्षा के कारण बंगाल ने धीरे-धीरे अपना महत्व खो दिया। मोदी ने कहा कि उन्होंने शुक्रवार को राज्य के विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि राज्य पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार है।

अन्य बातों के अलावा, प्रधानमंत्री ने पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर में स्थित रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन चरण (2 गुणा 660 मेगावाट) का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दामोदर घाटी निगम की यह कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना अत्यधिक कुशल एवं महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है।

नया प्लांट देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक कदम होगा। इसके अतिरिक्त, मेजिया थर्मल पावर स्टेशन की यूनिट सात और आठ की ग्रिप गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली पर आधारित होगी। लगभग 650 करोड़ रुपये की लागत से विकसित, एफजीडी प्रणाली ग्रिप गैसों से सल्फर डाइऑक्साइड को हटा देगी, स्वच्छ ग्रिप गैस का उत्पादन करेगी और जिप्सम बनाएगी, जिसका उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जा सकता है।

मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-12) (100 किमी) के फरक्का-रायगंज खंड के चार लेन की सडक़ परियोजना का भी अनावरण किया। लगभग 1,986 करोड़ रुपये की लागत से विकसित यह परियोजना यातायात की भीड़ को कम करेगी, कनेक्टिविटी में सुधार करेगी और उत्तर बंगाल तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देगी। प्रधानमंत्री ने 940 करोड़ रुपये से अधिक की चार रेल परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित कीं, जिनमें दामोदर-मोहिशिला रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजना, रामपुरहाट और मुरारई के बीच तीसरी लाइन, बाजारसौ-अजीमगंज रेल लाइन का दोहरीकरण, और अजीमगंज और मुर्शिदाबाद को जोडऩे वाली एक नई लाइन भी शामिल है। ये परियोजनाएं रेल कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी, माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करेंगी और क्षेत्र में आर्थिक और औद्योगिक विकास में योगदान देंगी।